

मुख्यमंत्री

राज्य सरकार ने आर.डी.जी. के मुद्दे पर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली से लौटने के बाद आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस बैठक में आर.डी.जी. बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वित्तीय घाटे के बावजूद राज्य सरकार न तो नौकरियां खत्म करेगी और न ही पुरानी पेंशन योजना बंद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान संवैधानिक अधिकार है और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान संसद सत्र के चलते वे जेपी नड्डा सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात नहीं कर पाए। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर आर.डी.जी. सहित संगठन के मुद्दों पर चर्चा की है।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य की मौजूदा आर्थिक बदहाली के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शिमला में आज पत्रकारा वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाए और लगातार फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया है। राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार ने गैर कानूनी तरीके से सीपीएस लगाए और सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की पैरवी करने के लिए वकीलों को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगमों व बोर्डों में बड़ी संख्या में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तैनात किए गए हैं और महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। बिंदल ने कहा कि आरडीजी बंद होने से नहीं राज्य सरकार के कुप्रबंधन से ही प्रदेश आज आर्थिक बदहाली की दहलीज पर पहुंच गया है।

अनुराग ठाकुर

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष के बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और केंद्र सरकार का ये सर्वकल्याणकारी बजट है। उन्होंने आज लोकसभा में अगले वित्त वर्ष के बजट पर बोलते हुए कहा कि इसमें बैंकिंग, उद्योग, स्वास्थ्य, महिला विकास, शिक्षा, कृषि, रक्षा और ऊर्जा जैसे 12 क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में जहां कुल 3 सौ 87 मैडिकल कॉलेज थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 7 सौ 6 हो गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सल हैल्थकेयर स्कीम है।

सुरेश कश्यप

सांसद सुरेश कश्यप ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हिमाचल में दूरसंचार सेवाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बी.एस.एन.एल. नेटवर्क की समस्या है और निगम में स्टॉफ की भी भारी कमी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि स्टॉफ की कमी के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क रखरखाव और सेवा बहाली में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके जवाब में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष कनेक्टिविटी योजनाएं चलाई जा रही हैं और फुल सेचुरेशन योजना के तहत देश के लगभग 3 हजार गांव चिन्हित किए गए हैं जहां 21 हजार टॉवर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक 17 हजार टॉवर लगाए जा चुके हैं और शतप्रतिशत कनेक्टिविटी के लक्ष्य को जल्द पूरा किया जाएगा।